अनंता से बदलेगा उज्जैन का भविष्य, नौकरियां मिलेंगी अनन्त

- आईटी पार्क रोकेगा युवाओं का पलायन
- इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर बन रही बिल्डिंग
- रोजगार, स्टार्टअप और नवाचार का केंद्र बनेगा आईटी पार्क

नवभारत न्यूज

उज्जैन. महाकाल की नगरी अब केवल धर्म और आस्था तक सीमित नहीं रह जाएगी, बल्कि आने वाले समय में यह शहर उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अपनी सशक्त पहचान बनाएगा. मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित किया जा रहा आईटी पार्क अनंता उज्जैन के युवाओं के लिए रोजगार और भविष्य की नई राह खोलने जा रहा है.

पढ़े-लिखे युवाओं को अब नौकरी की तलाश में दूसरे शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह आईटी पार्क स्थानीय स्तर पर ही बड़े अवसर उपलब्ध कराएगा.

दूसरा चरण देगा संबल- एमपीआईडीसी द्वारा आईटी पार्क अनंता के दूसरे चरण के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके लिए लगभग 45.98 करोड़ रुपए का टेंडर जारी होते ही शहर और पूरे मालवांचल में उम्मीद की नई किरण जगी है. परियोजना को उज्जैन के आर्थिक विकास की रीढ़ के रूप में देखा जा रहा है, जहां बड़े कॉर्पोरेट कार्यालय, आईटी और डिजिटल कंपनियों के लिए स्पेस, स्टार्टअप और इनक्यूबेशन सुविधाएं, आधुनिक कार्यस्थल, सम्मेलन कक्ष, पर्याप्त पार्किंग, कैफेटेरिया और सहयोगी गतिविधियों के क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं. इसका उद्देश्य केवल

भवन निर्माण नहीं, बल्कि एक ऐसा तकनीकी और औद्योगिक वातावरण तैयार करना है, जो युवाओं को सीधे रोजगार और नवाचार से जोड़े. इंजीनियरिंग कॉलेज पर ले रहा आकर- इंजीनियरिंग कॉलेज के तिराहे पर बन रहा यह आईटी पार्क अब तेजी से आकार ले रहा है. पहले चरण के कार्य की शुरुआत 21 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा भूमि पूजन के साथ की गई थी. वर्तमान में पहले चरण का करीब 30 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. एमपीआईडीसी द्वारा निर्माण कार्य की नियमित निगरानी की जा रही है ताकि तय समय-सीमा में परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके और दूसरे चरण में किसी प्रकार की देरी न हो.

धर्म नगरी बन रही उद्योग नगरी-अभी तक उज्जैन की वैश्विक पहचान महाकाल की नगरी के रूप में रही है, लेकिन आईटी पार्क के पूर्ण होने के बाद शहर को एक नई पहचान भी मिलेगी. उज्जैन अब आईटी और उद्योग नगरी के रूप में भी जाना जाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना से न केवल आईटी और डिजिटल सेवाओं में रोजगार बढ़ेगा, बल्कि रियल एस्टेट, होटल व्यवसाय, परिवहन और शैक्षणिक संस्थानों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

कमिश्नर, कलेक्टर और निदेशक कर रहे मॉनिटरिंग

आईटी पार्क अनंता को मिशन मोड में विकसित किया जा रहा है, ताकि यह उज्जैन के युवाओं के सपनों को साकार कर सके। यह परियोजना बेरोजगारी की समस्या को कम करने, प्रतिभा पलायन रोकने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाएगी. महाकाल की नगरी में उद्योग और तकनीक का यह नया अध्याय उज्जैन को भविष्य के विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने वाला सिद्ध होगा. सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह, उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौर लगातार आईटी पार्क के निर्माण कार्य की मॉनीटरिंग कर रहे हैं.

एक नजर में

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन आज

ग्वालियर. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सहभागिता एवं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की उपस्थिति में 25 दिसंबर को ग्वालियर के मेला ग्राउंड में अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट का राज्य स्तरीय आयोजन किया जाएगा. यह समिट पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनके विकासवादी दृष्टिकोण, सुशासन की अवधारणा एवं राष्ट्र निर्माण के संकल्प को समर्पित रहेगी. इस आयोजन के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन और मध्यप्रदेश को विकास की नई ऊँचाइयों तक ले जाने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी .गृह मंत्री के करकमलों से ग्वालियर व्यापार मेला का शुभारंभ भी होगा.

सूजी और मैदा के पैकेट में मिले कीड़े

ग्वालियर. ग्वालियर में सूजी और मैदा के पैकेट में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है. कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अजीत भदौरिया ने इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया. यह घटना मिनी मार्ट से 7 दिसंबर को खरीदे गए उत्पादों से संबंधित है. भदौरिया के अनुसार, जब इन पैकेटों का घर में इस्तेमाल किया गया, तो उनमें कीड़े रेंगते हुए पाए गए. उन्होंने इस संबंध में मंगलवार को कलेक्टर और खाद्य विभाग से लिखित शिकायत की है.

पटवारी ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल

चुनाव में किए वादों को पूरा करने के बजाय सरकार जनता को गुमराह कर रही

विशेष संवाददाता

भोपाल, 23 दिसंबर. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं जताईं. उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार के दो वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन विज़न डॉक्यूमेंट और चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने के बजाय सरकार जनता को गुमराह कर रही है.

प्रदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा के दौरे का स्वागत करते हुए पटवारी ने मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर

पाँच सीधे सवाल उठाए. उन्होंने नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों में निजी भागीदारी पर सवाल खड़े किए और छिंदवाड़ा में दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग की.

> प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वह इलाज, न्याय और सुरक्षा देने के बजाय प्रतीकात्मक मुद्दों में उलझी हुई है। पटवारी ने आरोप लगाया कि पहले बनाए गए शासकीय अस्पतालों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है और चेतावनी दी कि प्रदेश अघोषित स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है, जिस पर सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

इसके अलावा इंदौर के शासकीय अस्पताल में बच्चों को चूहों द्वारा काटे जाने जैसी अमानवीय घटनाओं की कड़ी निंदा की. पटवारी ने कथित 'साइंस हाउस' घोटाले में फर्जी जांचों के जरिए सरकारी धन की लूट का मुद्दा भी उठाया तथा मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की भारी कमी पर सवाल किए.

उन्होंने कहा कि ज़हरीली दवाएं, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाए जाने, आईसीयू में आग लगने और नवजातों की उपेक्षा जैसी घटनाएं सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती हैं. पटवारी का दावा है कि यदि 23,535 करोड़ रुपये के स्वास्थ्य बजट का ईमानदारी और पारदर्शिता से उपयोग किया जाए, तो प्रदेश के हर नागरिक को मुफ्त इलाज संभव है.

संगठित भर्ती घोटाले का आरोप लगाया

विशेष संवाददाता

भोपाल, 23 दिसंबर. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव अमित शर्मा ने मंगलवार को भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि पिछले दो दशकों से सत्ता में रहने के बावजूद राज्य में भ्रष्टाचार और कागजी विकास ही देखने को मिला है.

एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि भाजपा द्वारा स्वर्णिम और विकसित मध्य प्रदेश के किए गए दावे लगातार सामने आ रहे घोटालों के कारण खोखले साबित हो गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि रीवा जिले की डभौरा नगर परिषद में व्यापम घोटाले की तर्ज पर एक संगठित भर्ती घोटाला किया गया. यह नगर

परिषद वर्ष 2020 में सात ग्राम पंचायतों को मिलाकर गठित की गई थी. शर्मा के अनुसार, इस मामले में स्थानीय भाजपा विधायक, तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ), संयुक्त संचालक तथा अन्य अधिकारियों की सीधी संलिप्तता रही है. उन्होंने कहा कि नगर परिषद के गठन के समय वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों के समायोजन और नियमितीकरण के वैधानिक अधिकारों को नजरअंदाज किया गया.

बिना विज्ञापन 50 भर्तियां करने का आरोप

विधायक के परिजनों, निजी सहायक तथा वरिष्ठ अधिकारियों के परिवारजनों की अवैध नियुक्तियां की गईं. शर्मा ने आरोप लगाया कि जहां केवल 21 पद स्वीकृत थे, वहां बिना विज्ञापन, आरक्षण, रोस्टर और स्वीकृति के 50 भर्तियां की. फर्जी प्रस्तावों, समितियों और पे-स्लिप के माध्यम से 2 से 5 करोड़ के गबन का भी आरोप लगाया. जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उन्होंने स्वतंत्र जांच, अवैध नियुक्तियों को रद्द करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

राख की लैंडफिलिंग करने पर लगी रोक हटी

जहरीला कचरा हाईकोर्ट ने अस्थाई तौर पर लिया आदेश वापस

जबलपुर, 23 दिसंबर. यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का विनष्टीकरण से निकली राख की लैंडफिलिंग लगी रोक के आदेश को हाईकोर्ट ने अस्थाई रूप से वापस ले लिया है. सरकार के द्वारा उक्त आदेश की समीक्षा करने हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया गया था.

हाईकोर्ट जस्टिस विवेक कुमार सिंह तथा जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की युगलपीठ ने आवेदन की सुनवाई करते हुए उक्त आदेश जारी किये. युगलपीठ ने सरकार को पूर्व में पारित आदेश के अनुसार कार्यवाही करने निर्देश जारी किये है. गौरतलब है कि साल 2004 में आलोक प्रताप सिंह ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में कर रही है. पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया था कि जहरीले कचरे का विनष्टीकरण सफलतापूर्वक पीथमपुर स्थित सुविधा केंद्र में कर दिया गया है. जहरीले कचरे से लगभग 900 मीट्रिक टन राख व अवशेष एकत्रित हुआ है.

> हाईकोर्ट में एक अन्य याचिका दायर करते हुए कहा गया था कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की राख में रेडियो एक्टिव पदार्थ सक्रिय हैं, जो चिंता का विषय है. राख में मरकरी है, जिसे नष्ट करने की तकनीक सिर्फ जापान व जर्मनी के पास है. हाईकोर्ट ने उक्त याचिका की सुनवाई मुख्य याचिका के साथ किये जाने के आदेश जारी किये थे. हाईकोर्ट ने 8 अक्टूबर 2025 को जारी अपने आदेश में कहा गया था कि पूर्व में पारित आदेश के बावजूद भी जहरीले कचरे की राख की लैंडफिलिंग के लिए सरकार के द्वारा दूसरे स्थान के संबंध में जानकारी नहीं दी गयी. सरकार के द्वारा इंसानों की आबादी से सिर्फ 500 मीटर दूर लैंड फिलिंग का स्थान निर्धारित किया गया है.

एनएसयूआई ने नेताओं का किया पुतला दहन

भोपाल, 23 दिसंबर. भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन भोपाल ने सोमवार को महिलाओं के प्रति भाजपा नेताओं द्वारा दिए जा रहे कथित अपमानजनक, अशोभनीय और निंदनीय बयानों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया. एनएसयूआई प्रदेश महासचिव सैयद अल्तमस के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा की महिला-विरोधी मानसिकता का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया. एनएसयूआई भोपाल जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं की बार-बार की गई टिप्पणियां पार्टी की लंबे समय से चली आ रही पितृसत्तात्मक और महिला-विरोधी सोच को उजागर करती हैं.

नलों से घरों में पानी आने से बहनों का बच रहा है समय

- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मंत्री संपतिया उईके ने कहा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 23 दिसंबर. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उईके ने जल जीवन मिशन को लेकर साफ किया है कि उनका विभाग केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए समय से पहले ही मिशन का काम पूरा कर लेगा.

उन्होंने मिशन का काम पूरा होने के फायदे गिनाते हुए कहा कि मैं भी कभी सिर में रखकर पानी लाती थी, जंगल के खेड़े में रहते थे. दो किमी दूर से गुंडी के ऊपर गुंडी रखकर तालाब से पानी लाती थी. वे बच्चियां जो पानी भरने के कारण समय पर स्कूल नहीं जा पाती थीं,

वे बहनें सुबह-शाम पानी भरने में व्यस्त रहने के कारण दूसरा कोई काम नहीं कर पाती थी, अब टोटी चालू करने पर घर के आंगन में ही पानी मिल रहा है, तो इससे बहनों का काम समय पर हो रहा है, उनका समय बच रहा है और इस बचे हुए समय का उपयोग बहनें दूसरे कामों में कर रही हैं, बहनें अब पार्लर, सिलाई-कढ़ाई केंद्र, किराना दुकान खोल रही हैं तो दूसरे तरह के स्वरोजगार से भी अपनी आजीविका चलाने लगी है. पीएचई मंत्री ने मंगलवार को दो वर्ष की उपलब्धियों का ब्यौरा पत्रकार वार्ता के दौरान दिया. इस दौरान उन्होंने मिशन के कामों के के पूरा होने के बाद होने वाले फायदे गिनाए. उन्होंने ये भी बताया कि विभाग में पानी को लेकर जो भी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में की गई, उन शिकायतों के निराकरण में विभाग को ए प्लस मिला है. उन्होंने बताया कि उज्जैन संभाग पहला संभाग है, जहां के सभी जिलों में मिशन का काम 100 फीसदी पूरा कर लिया गया है. बाकी संभागों का काम भी समय पर पूरा कर लिया जाएगा. दो वर्ष में 13.69 लाख परिवार को नए नल कनेक्शन दिए श्रीमती उइके ने कहा कि विगत दो वर्षों में 13 लाख 69 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को नए नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं.

पेज एक का शेष

चार उपाध्यक्ष बनाने की तैयारी में कांग्रेस

बल्कि इसके तहत संगठन को और धारदार व जवाबदेह बनाने का प्रयास किया जाएगा. चर्चा है कि सांगठनिक अनुभव प्राप्त कर चुके अपेक्षाकृत युवा नेताओं को उपाध्यक्ष बनाकर पार्टी रणनीतिकार युवा मतदाताओं के बीच सार्थक संदेश देते हुए उन्हें पुन: कांग्रेसी विचारधारा के साथ जोडने का प्रयास करेंगे. सूत्रों की मानें तो पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, पृथ्वीराज चौहान, भूपेन्द्र हुड्डा, भूपेश बघेल तथा वी नारायण सामी के साथ-साथ पार्टी महासचिव सचिन पायलट, पूर्व पार्टी महासचिव तारिक अनवर जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम में से ही किसी चार को पार्टी उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है. सूत्रों की मानें तो बहुस्तरीय चुनावों में लगातार पराजय सामना कर रही पार्टी ने अपने परंपरागत रणनीति में सुधारात्मक बदलाव करने की तैयारी आरंभ कर दी है. पार्टी रणनीतिकारों द्वारा संगठन सृजन के माध्यम से जहां एक तरफ जमीनी स्तर तक मजबूत संगठन तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर चुनावी लडाई में बेहतर परिणाम पाने के उदेश्य से उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया और प्रचार नीति में व्यापक बदलाव किया जाएगा.

वित्त विभाग के परिपत्र में हो बदलाव : कर्मचारी संघ

विशेष संवाददाता

भोपाल, 23 दिसंबर. मंत्रालय सेवा अधिकारी/कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार से वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र की कुछ धाराओं की समीक्षा कर उनमें संशोधन करने की मांग की है.

यह परिपत्र 16 दिसंबर को हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में जारी किया गया था. संघ अध्यक्ष सुधीर नायक ने प्रेस वक्तव्य में कहा कि कार्यभारित एवं स्थायी आकस्मिकता निधि कर्मचारियों को डाइंग काडर घोषित कर दिया गया है, लेकिन वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को पहले नियमित किया जाना चाहिए था. उन्होंने कहा कि इसके बाद भले ही संवर्ग को समाप्त किया जाता, तो यह अधिक कर्मचारी-हितैषी निर्णय होता. संघ ने कहा कि नियमित पदों पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि लंबे समय से पदोन्नतियां रुकी हुई हैं और रिक्त पद उपलब्ध नहीं हैं. इसलिए अनुकंपा नियुक्ति सांख्येतर पदों पर दिए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60